RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 30 NOVEMBER TO 06 DECEMBER 2022 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 08 ■ अंक 11 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

ओएनजीसी गैस की कीमत पांच साल के लिए 6.5 डॉलर Page 2

एक दिसंबर से बदल जाएंगे ये नियम, जानें किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी? Page 3

देश की सबसे छोटी ई-कार लॉन्च, कीमत 5 लाख से भी कम, सिंगल चार्ज में जाएगी 200 किमी Page 5

editoria!

महत्वपूर्ण अवसर

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह जी-20 की अध्यक्षता भारत के लिए एक अहम मौका है. इसे रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को वैश्विक हित पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा देश की विविधता को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए. इस समूह के सदस्य देशों के वरिष्ठ कूटनीतिकों के समक्ष भारत ने अपनी प्राथमिकताओं को रखा है, जिसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु संबंधी कार्यवाही, स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति और बहुपक्षीय सुधार आदि आवश्यक विषय शामिल हैं. अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर हुई इस बैठक में सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के 40 राजदूत, उच्चायुक्त एवं प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है. भारत के ओर से जी-20 अध्यक्षता के प्रभारी अमिताभ कांत ने इस अवसर पर बाली में दिये गये प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुख होगी. आगामी एक दिसंबर से औपचारिक रूप से अध्यक्षता का एक वर्षीय कार्यकाल प्रारंभ हो रहा है. पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगला जी-20 के मुख्य समन्वयक बनाये गये हैं. अगले साल के अंतिम हिस्से में जी-20 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जायेगा. इस एक साल में कई तरह की बैठकें होंगी, जिसमें सदस्य और अतिथि देशों के मंत्री, अधिकारी, उद्यमी, कारोबारी आदि भागीदारी करेंगे. बीते कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अलग-अलग शहरों में राष्ट्राध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों का स्वागत करने की नवीन परंपरा का प्रारंभ किया है. मंत्रिस्तरीय बैठकें तथा बहुपक्षीय आयोजन भी अब अक्सर अन्य शहरों में होने लगे हैं. इस परंपरा से आयोजन स्थलों के विकास में तो सहायता मिलती ही है, साथ ही अन्य देशों से आये प्रतिनिधि भारत की व्यापकता, समृद्ध विरासत तथा सांस्कृतिक विविधता से भी परिचित होते हैं. जी-20 के आयोजनों को भी देश के कई शहरों में करने की योजना है, जिसकी एक अच्छी शुरुआत अंडमान से हुई है. दुनिया अनेक संकटों का सामना कर रही है. महामारी से उबरने के प्रयास हो ही रहे थे कि रूस-यूक्रेन युद्ध ने ऊर्जा और खाद्य संकट जैसी मुश्किलों को ला खड़ा किया है. अनेक देश गृहयुद्ध की चपेट में हैं, तो युद्ध की आशंकाएं भी हैं. जलवायु परिवर्तन की चुनौती मानवता के अस्तित्व के लिए ही प्रश्नचिन्ह बन चुकी है. कारोबारी संबंधों पर भू-राजनीतिक तनावों का घना साया है. ऐसी स्थिति में जी-20 समाधान की राह निकालने का प्रभावशाली मंच साबित हो सकता है.

14 रु. तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल-डीजल

कच्चे तेल के दाम गिरे, कस्टमर-कंपनी दोनों को फायदा

नई दिल्ली। एजेंसी

कच्चे तेल के दाम गिरने के चलते देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 14 रुपए तक की कमी आ सकती है। इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल (ब्रेंट) की कीमत जनवरी से निचले स्तर पर हैं। यह अब 81 डॉलर से नीचे आ गया है। अमेरिकी क्रूड 74 डॉलर प्रति बैरल के करीब है।

मई के बाद पहली बार पेट्रोल-डीजल के दाम घट सकते हैं

खास तौर पर कच्चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट से भारतीय रिफाइनरी के लिए कच्चे तेल की औसत कीमत (इंडियन बास्केट) घटकर 82 डॉलर प्रति बैरल रह गई है। मार्च में ये 112.8 डॉलर थी। इस हिसाब से 8 महीने में रिफाइनिंग कंपनियों के लिए कच्चे तेल के दाम 31 डॉलर (27%) कम हो गए हैं। एसएमसी ग्लोबल के मुताबिक, क्रूड में 1 डॉलर गिरावट आने पर देश की तेल कंपनियों को रिफाइनिंग पर प्रति लीटर 45 पैसे की बचत होती है। इस हिसाब से पेट्रोल-डीजल के दाम 14 रु. प्रति लीटर तक कम होने चाहिए। हालांकि, विशेषज्ञों के मुताबिक पूरी कटौती एक बार में नहीं होगी।

जानिए पेट्रोल-डीजल के दाम घटने की 3 वजह

1. ऑयल कंपनियों को प्रति बैरल 245 रुपए की बचत

अभी देश में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं, उसके हिसाब से क्रूड ऑयल का इंडियन बास्केट करीब 85 डॉलर प्रति बैरल होना चाहिए, लेकिन ये 82 डॉलर के आसपास आ गया है। इस भाव पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को प्रति बैरल (159 लीटर) रिफाइनिंग पर करीब 245 रुपए की बचत होगी।

2. ऑयल कंपनियों को हो रहा घाटा अब खत्म

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल की बिक्री पर मुनाफा होने लगा है, लेकिन डीजल पर अब भी 4 रुपए प्रति लीटर घाटा हो रहा है। तब से अब तक ब्रेंट क्रूड करीब 10% सस्ता हो गया है। ऐसे में कंपनियां डीजल पर भी मुनाफे में आ गई हैं।

3. 70 डॉलर की तरफ बढ़ रहा कच्चा तेल, मिलेगी राहत

पेट्रोलियम एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा ने कहा कि ब्रेंट तेजी से 70 डॉलर की तरफ बढ़ रहा है। इससे पेट्रोल-डीजल के दाम जरूर कम होंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। तेल आयात से लेकर रिफाइनिंग तक का साइकल 30 दिन का होता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम घटने के एक माह बाद असर दिखता है।

भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल करता है आयात

हम अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से खरीदते हैं। इसकी कीमत हमें डॉलर में चुकानी होती है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने और डॉलर के मजबूत होने से पेट्रोल-डीजल महंगे होने लगते हैं। कच्चा तेल बैरल में आता है। एक बैरल यानी 159 लीटर कच्चा तेल होता है।

भारत में कैसे तय होती हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें?

जून 2010 तक सरकार पेट्रोल की कीमत निर्धारित करती थी और हर 15 दिन में इसे बदला जाता था। 26 जून 2010 के बाद सरकार ने पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण ऑयल कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया। इसी तरह अक्टूबर 2014 तक डीजल की कीमत भी सरकार निर्धारित करती थी। 19 अक्टूबर 2014 से सरकार ने ये काम भी ऑयल कंपनियों को सौंप दिया। अभी ऑयल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत, एक्सचेंज रेट, टैक्स, पेट्रोल-डीजल के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और बाकी कई चीजों को ध्यान में रखते हुए रोजाना पेट्रोल-डीजल की कीमत निर्धारित करती हैं।

ओएनजीसी गैस की कीमत पांच साल के लिए 6.5 डॉलर

रिलायंस-बीपी के लिए मूल्य में बदलाव नहीं

नयी दिल्ली। एजेंसी

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा पुराने क्षेत्रों से निकलने वाली प्राकृतिक गैस पर पांच साल के लिए मूल्य सीमा लागू की जा सकती है। सरकार द्वारा किरीट पारेख की अगुवाई में नियुक्त गैस मूल्य समीक्षा समिति ने इसकी सिफारिश की है। सीएनजी और पाइपलाइन से आने वाली रसोई गैस पीएनजी की कीमतों में नरमी लाने के लिए ऐसा किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) को चार डॉलर प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट (प्रति इकाई) के न्यूनतम मूल्य और 8.57 डॉलर की मौजूदा दर के मुकाबले अब अधिकतम 6.5 डॉलर का भुगतान किया जाएगा। मामले से जुड़े तीन सूत्रों ने यह जानकारी दी। हालांकि, मुश्किल क्षेत्रों से निकलने वाली गैस के लिए मूल्य निर्धारण फॉर्मूले को नहीं बदला जाएगा। मूल्य निर्धारण की यह व्यवस्था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केजी-डी6 क्षेत्र और ब्रिटेन की इसकी भागीदार बीपी पीएलसी के मुश्किल क्षेत्रों पर लागू होती है। पारेख समिति को "भारत में गैस-आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बाजार-उन्मुख, पारदर्शी और भरोसेमंद मूल्य निर्धारण व्यवस्था" सुनिश्चित करने के लिए सुझाव देने का काम सौंपा गया था। समिति को यह भी तय करना था कि अंतिम उपभोक्ता को उचित मूल्य पर गैस मिले। उन्होंने कहा कि न्यूनतम और नियंत्रित मूल्य पांच साल के लिए होगा और इसकी हर साल समीक्षा की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कीमतें उत्पादन लागत से नीचे नहीं गिरेंगी, जैसा कि पिछले साल हुआ था। या मौजूदा दरों की तरह रिकॉर्ड ऊंचाई तक भी नहीं बढ़ेंगी। सूत्रों ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर खोज और उत्पादन (ईएंडपी) में निवेश की चिंताओं को भी दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बाजार आधारित मूल्य निर्धारण से नए निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और वैश्विक कंपनियां यहां आएंगी। सूत्रों ने कहा कि गैस के आवंटन में शहरी गैस को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी। यह क्षेत्र 'शून्य कटौती' श्रेणी में होगा, जिसका अर्थ है कि उत्पादन में गिरावट के मामले में पहले अन्य उपभोक्ताओं की आपूर्ति में कटौती की जाएगी। योजना आयोग के पूर्व सदस्य किरीट एस पारेख की अध्यक्षता वाली समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रही है और इसे अगले कुछ दिनों में सरकार को सौंप दिया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय इन सिफारिशों की समीक्षा के बाद इसे मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजेगा।

सरकार को ओएनजीसी से 5,001 करोड़ रुपये का लाभांश मिला

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) से लाभांश के रूप में 5,001 करोड़ रुपये मिले है। इस तरह चालू वित्त वर्ष में सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) से कुल 23,797 करोड़ रुपये का लाभांश मिल चुका है। निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने ट्वीट किया,"सरकार को ओएनजीसी से लाभांश के रूप में करीब 5,001 करोड़ रुपये मिले हैं।"

दीपम ने 2020 में सीपीएसई को एक सुसंगत लाभांश नीति का पालन करने और लाभप्रदता, निवेश की आवश्यकताओं, नकद/आरक्षित और निवल मूल्य जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए उच्च लाभांश का भुगतान करने का प्रयास करने की सलाह दी थी।

दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीएसई को कर के बाद लाभ का 30 प्रतिशत (पीएटी) या निवल मूल्य का पांच प्रतिशत, जो भी अधिक हो, का न्यूनतम वार्षिक लाभांश देना आवश्यक है। दीपम की वेबसाइट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में अबतक कुल लाभांश प्राप्ति 23,796.55 करोड़ रुपये हो गई हैं।

रुपया 34 पैसे बढ़कर 81.38 प्रति डॉलर पर

मुंबई। एजेंसी

विदेशी बाजारों में डॉलर के कमजोर होने और घरेलू शेयर बाजारों में तेजी के बीच निवेशकों की जोखिम लेने की धारणा में सुधार से अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया बुधवार को 34 पैसे के सुधार के साथ 81.38 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 81.63 पर खुला। कारोबार के दौरान यह 81.38 के उच्चस्तर और 81.64 के निचले स्तर तक गया। अंत में रुपया 34 पैसे की तेजी के साथ 81.38 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपये का पिछला बंद भाव 81.72 प्रति डॉलर था। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषक दिलीप परमार ने कहा कि जोखिम वाली आस्तियों की धारणा में सुधार, कच्चे तेल की कम कीमतें तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों का निवेश बढ़ने के बाद पिछले 11 महीनों में भारतीय रुपये में पहली मासिक बढ़त दर्ज की गई। परमार ने कहा, "यह महीने के अंत में 1.6 प्रतिशत ऊंचा बंद होने की ओर अग्रसर है जो अगस्त, 2021 के बाद से सबसे बड़ा लाभ होगा।" इस बीच, दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की कमजोरी या मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.29 प्रतिशत की गिरावट के साथ 106.51 पर रह गया। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 2.13 प्रतिशत बढ़कर 84.80 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

दूसरी तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), अप्रैल-अक्टूबर के लिए राजकोषीय घाटे के आंकड़े और अक्टूबर के लिए बुनियादी उद्योगों के आंकड़े आज जारी किए जाने हैं। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 417.81 अंक बढ़कर 63,099.65 अंक पर बंद हुआ। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) पूंजी बाजार में शुद्ध लिवाल रहे और उन्होंने मंगलवार को 1,241.57 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर ख़रीदे।

आरबीआई का 1 दिसंबर से प्रायोगिक आधार पर खुदरा डिजिटल रुपया शुरू करने की घोषणा की

पहले चरण में 4 बैंक और 4 शहर शामिल, दूसरे चरण में इंदौर मे होगा लागू...

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली दिसंबर से प्रायोगिक आधार पर खुदरा डिजिटल रुपया शुरू करने की घोषणा की है। रिजर्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इसके लिए आठ बैंकों की पहचान की गई है। पहले चरण में इसकी शुरूआत चार शहरों में भारतीय स्टेट बैंक, आई सी आई सी आई बैंक, यस बैंक और आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक से की जाएगी। बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एच डी एफ सी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक सहित चार और बैंक इसमें शामिल किए जायेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लाए गए ई ?-R 1 दिसंबर से देश के हासिल किया जा सकेगा। नए करेंसी के उपयोग के लिए लोगों को बैंकों के द्वारा मुहैया किए जाने वाले वॉलेट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। प्रायोगिक आधार पर डिजिटल रूपये की शुरूआत मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर शहरों में की जायेगी। बाद में इसका विस्तार अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला तक किया जाएगा। आवश्यक होने पर इसका दायरा धीरे-धीरे बढ़ाया जा सकता है। प्रायोगिक आधार पर डिजिटल रूपया ग्राहकों और व्यापारियों के क्लोज्ड यूजर ग्रुप में चुनिंदा स्थानों पर उपलब्ध होगा। डिजिटल रुपया एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा और इसकी कानूनी वैधता होगी। उपयोगकर्ता मोबाइल फोन पर बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये डिजिटल वॉलेट के माध्यम से डिजिटल रुपये का लेन-देन कर सकेंगे। व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति से कारोबारी दोनों के बीच डिजिटल रूपये में लेन-देन संभव होगा। क्यू आर कोड का उपयोग करके व्यापारियों को भुगतान किया जा सकेगा।

पैकिंग मटेरियल पर कम हो GST, केंद्रीय वित्त मंत्रालय की बैठक में की मांग

नयी दिल्ली। एजेंसी

साल 2023-24 के बजट के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से एक बैठक रखी गई। यह बैठक राजधानी दिल्ली में हुई। बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी बतौर वित्त मंत्री इस बैठक में शामिल हुए. बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पैकिंग मटेरियल में बढ़ाए गए जीएसटी (उएऊ) को 18 फीसदी से कम कर 12 फीसदी करने की मांग उठाई है।

गौरतलब है कि सेब की पैकिंग करने में जिस मटेरियल का इस्तेमाल होता है, उस पर 18 फीसदी जीएसटी वसूला जा रहा है। इससे बागवान में भी खासा रोष है। हालांकि, प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर 18 में 6 फीसदी जीएसटी को एचपीएमसी के जरिए भुगतान करने की बात कही थी, लेकिन प्रदेश सरकार चाहती है कि केंद्र सरकार के स्तर पर यह मसला सुलझ जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश के बागानों को राहत मिल सके।

GST कंपनसेशन बहाल करने की मांग

सभी राज्यों के लिए जीएसटी कंपनसेशन एक बड़ा मुद्दा है। केंद्र के सहयोग से चलने वाले हिमाचल प्रदेश के लिए इसकी महत्ता और भी अधिक हो जाती है। जीएसटी कंपनसेशन न मिलने की वजह से हिमाचल प्रदेश को हर साल 4 हजार करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ रहा है। 72 हजार करोड़ के कर्ज तले दबे हिमाचल प्रदेश के लिए यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। ऐसे में अगर सरकार जीएसटी कंपनसेशन बहाल करती है, तो इससे हिमाचल प्रदेश को बड़ी राहत मिलेगी. हालांकि, यह एजेंडा बजट बैठक की जगह जीएसटी काउंसिल के अधिकार क्षेत्र में आता है।

केंद्र पोषित राज्य है हिमाचल प्रदेश

बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हेली टैक्सी के साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के तहत मिलने वाली कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी की शेष देनदारी को पूरा करने के साथ इसे बहाल करने की भी मांग उठाई है। हिमाचल प्रदेश एक केंद्रीय पोषित राज्य है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए केंद्र के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। हिमाचल प्रदेश में आर्थिकी के अपने साधन नाम मात्र के हैं। हिमाचल प्रदेश का अधिकतम के बजट का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों की तनख्वाह और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन देने में चला जाता है। ऐसे में केंद्रीय बजट से हिमाचल प्रदेश को बड़ी उम्मीदें रहती हैं। केंद्र की बड़ी योजनाओं से ही हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य पूरे किए जाते हैं।

यूपीआई ट्रांजेक्शन से हुई वृद्धि

टीडीएस के नए रजिस्ट्रेशन में पिछले अप्रैल से अक्टूबर की अपेक्षा 7 गुना वृद्धि, जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

मप्र में जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग की मुहिम रंग लाई है। इसके चलते टीडीएस की श्रेणी वाले करदाताओं के नवीन रजिस्ट्रेशन की संख्या में खासी वृद्धि हुई है। पिछले साल विभाग द्वारा अप्रैल से अक्टूबर 2021 तक टीडीएस की श्रेणी में 534 पंजीयन करवाए गए थे, जो इस साल इसी अवधि में बढ़कर 3,508 हो गए हैं। यानी इसमें करीब सात गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है।

इसके पीछे बड़ा कारण ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और प्राधिकरणों से पंजीयन करवाना रहा। टीडीएस के अलावा नए पंजीयन की संख्या में भी इजाफा हुआ है। ये पिछले साल 37,077 थे। इसी अवधि में इस साल 45,276 हो गए हैं। साधारण पंजीयन लेने वालों की संख्या भी पिछले साथ के मुकाबले बढ़ी है।

पिछले अप्रैल से अक्टूबर तक 34,528 लोगों ने नए पंजीयन लिए, जबकि इस साल इसकी संख्या 39,525 रही है। कैजुअल

पंजीयन की संख्या भी 82 से बढ़कर 157 हो गई है। सीए कीर्ति जोशी ने बताया कि संख्या बढ़ने के पीछे बड़ा कारण बढ़ते यूपीआई ट्रांजेक्शन भी हैं। इससे पहले कई व्यवसायी नकद व्यवहार कर आसानी से अपना टर्नओवर छिपा लेते थे, लेकिन अब ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं है। बैंक स्टेटमेंट से सभी यूपीआई ट्रांजेक्शन साफ नजर आते हैं और टर्नओवर का बेहतर आकलन हो पता है।

रजिस्ट्रेशन एसओपी से सात दिन में दिए जाने वाले रजिस्ट्रेशनों की संख्या भी बढ़ी

इस साल विभाग द्वारा नया पंजीयन कराने की प्रक्रिया आसान करने के लिए एसओपी जारी कर जरूरी दस्तावेजों की संख्या कम कर दी गई थी। वाणिज्यिक कर आयुक्त लोकेश कुमार जाटव ने बताया, दो महीने पहले एसओपी लागू करने के बाद 7 दिन के भीतर दिए जाने वाले पंजीयन की संख्या में पिछले साल के मुकाबले 9३ वृद्धि हुई है। अब 3 दिन में होंगे आवेदन अप्रूव, पहले 7 दिन लगते थे- विभाग का कहना है कि ज्यादातर मामलों में सात दिन के भीतर पंजीयन दिया गया है। आने वाले समय में जल्द ही मात्र तीन दिन में पंजीयन के सभी आवेदन अप्रूव करने का लक्ष्य रखा गया है।

GST: केंद्र ने राज्यों को जीएसटी अनुदान के रूप में 17000 करोड़ रुपये जारी किए, महाराष्ट्र को मिले 2000 करोड़

मुंबई। एजेंसी

केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के बकाया जीएसटी अनुदान के लिए 17,000 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। अप्रैल से जून महीने के लिए यह राशि 24 नवंबर को जारी की गई है। सरकार की ओर से वर्ष 2022-23 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस 17,000 करोड़ रुपये की राशि के साथ अब तक 1,15,662 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

उधर, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई प्री-बजट बैठक के बाद कहा कि महाराष्ट्र को जीएसटी अनुदान के रूप में 2000 करोड़ रुपये मिले। कैग की ऑफिट के बाद महाराष्ट्र को 13,000 रुपये और मिलेंगे।

सरकार फेम-दो नियमों का उल्लघंन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी: मंत्री

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण की योजना (फेम) के तहत स्थानीयकरण नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने मंगलवार को यह बात कही। मंत्री ने एसोचैम के एक कार्यक्रम के बाद कहा कि नियमों के कथित उल्लंघन के लिए जिन कंपनियों की जांच चल रही है, उनको सब्सिडी का वितरण रोक दिया गया है। पांडेय ने कंपनियों के स्थानीयकरण मानदंडों का उल्लंघन करने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर कहा, ''हम इसकी कड़ाई से जांच कर रहे हैं। अगर नियमों का उल्लंघन किया गया है, तो जरूरी कार्रवाई की जाएगी।'' सूत्रों के अनुसार, फेम-दो योजना के तहत कथित उल्लंघन करने वाली कंपनियों...हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक, रिवॉल्ट, ओकोये, एम्पियर और जितेंद्र ईवी की पड़ताल की जा रही है। फेम-दो के तहत कम से कम 50 प्रतिशत माल की खरीद स्थानीय स्तर पर करना जरूरी है।

News यू केन USE

सरकार ने इसरो को विस्फोटक नियम के प्रावधानों से छूट दी

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को अंतरिक्ष रॉकेट के लिए ठोस प्रणोदक के निर्माण, भंडारण, उपयोग और परिवहन के लिए मंजूरी लेने के नियम से छूट दी है। ठोस प्रणोदक अंतरिक्ष रॉकेट में इस्तेमाल होने वाला मुख्य ईंधन है। सरकार ने कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के तहत यह फैसला किया। इससे पहले, इसरो को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की एक शाखा पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) से लाइसेंस लेना पड़ता था। डीपीआईआईटी की एक अधिसूचना के अनुसार यह छूट कुछ शर्तों के तहत दी गई है। शर्तों के अनुसार इसरो को विस्फोटकों के निर्माण, भंडारण, परिवहन और उपयोग के लिए विस्फोटक भंडारण एवं परिवहन समिति (एसटीईसी) के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

सरकार ने जैविक गैर-बासमती चावल के निर्यात से प्रतिबंध हटाया

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने घरेलू आपूर्ति बढ़ने से कीमतों के नरम पड़ने के बाद टूटे चावल सहित जैविक गैर-बासमती चावल के निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया है। सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से सितंबर की शुरुआत में टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद गैर-बासमती चावल के निर्यात पर 20 प्रतिशत का शुल्क लगाया गया, जिसका उद्देश्य खुदरा बाजारों में कीमतों के बढ़ने के बाद इनकी घरेलू आपूर्ति को बढ़ाना था। एक अधिसूचना में, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने मंगलवार को कहा कि जैविक गैर-बासमती टूटे चावल सहित जैविक गैर-बासमती चावल का निर्यात अब सितंबर में लागू प्रतिबंध से पहले के नियमों द्वारा प्रशासित होगा।

भारत-यूएई मुक्त व्यापार समझौते से परिधान क्षेत्र का निर्यात बढ़ेगा: एईपीसी

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच मुक्त व्यापार समझौता परिधान क्षेत्र को शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान कर रहा है और इससे उस देश में घरेलू निर्यात की हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। एईपीसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) ने कहा कि 20 से अधिक घरेलू निर्यातक अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए दुबई में अंतरराष्ट्रीय परिधान और वस्त्र मेले (आईएटीएफ) में भाग ले रहे हैं। एईपीसी के मेला और प्रदर्शनी चेयरमैन अशोक रजनी ने कहा कि भारत, चीन के बाद संयुक्त अरब अमीरात को तैयार कपड़ों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। उन्होंने कहा, "यूएई परंपरागत रूप से भारतीय परिधान निर्यात के लिए सबसे शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा है। भारतीय परिधान निर्यात के लिए शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करने वाले यूएई-भारत सीईपीए समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ यह हिस्सा और बढ़ने की उम्मीद है।"

भवरकुआँ पुलिस थाना का नाम बदलने की मांग

इंदौर। भवरकुआँ पुलिस थाना का नाम बदलकर 'द नायक टटंया भील पुलिस थाना' करने के लिए उच्च न्यायालय अधिवक्ता प्रवीण आलूने द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी एवं मान. मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा। जैसा कि पूर्व में भवरकुआं चौराहा का नाम बदलकर 'द नायक टटंया भील चौराहा' कर दिया गया है, जिससे कि अब भवरकुआं पुलिस थाना का नाम भी बदलकर 'द नायक टटंया भील पुलिस थाना' किये जाने की मांग की जाती है।

दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान: एसबीआई रिसर्च

मुंबई। एजेंसी

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शोध टीम ने विनिर्माण गतिविधियों में कमजोरी और मार्जिन के बढ़ते दबाव को देखते हुए जुलाई-सितंबर तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर 5.8 प्रतिशत कर दिया है। एसबीआई रिसर्च की तरफ से सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत रह सकती है जो औसत अनुमान से 0.30 प्रतिशत कम है। सरकार की तरफ से जुलाई-सितंबर, 2022 तिमाही के जीडीपी आंकड़े 30 नवंबर को जारी किए जाने हैं।

एसबीआई के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष की अगुवाई वाली टीम के मुताबिक, दूसरी तिमाही में बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र को छोड़कर बाकी कंपनियों के परिचालन लाभ में 14 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है जबकि एक साल पहले की समान

तिमाही में 35 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, आलोच्य तिमाही में इन कंपनियों के राजस्व में वृद्धि दर अच्छी रही है लेकिन उनके लाभ में एक साल पहले की तुलना में करीब 23 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसके अलावा बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र को छोड़कर अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के मार्जिन पर दबाव भी देखा गया है। उत्पादन लागत बढ़ने से कंपनियों का परिचालन मार्जिन दूसरी तिमाही में घटकर 10.9 प्रतिशत रह गया जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 17.7 प्रतिशत था।

एसबीआई रिसर्च का मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर औसत बाजार अनुमान (6.1 प्रतिशत) से कहीं कम 5.8 प्रतिशत रह सकती है। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष की समूची अवधि में वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रह सकती है जो भारतीय रिजर्व बैंक के पिछले अनुमान से 0.20 प्रतिशत कम है। एसबीआई रिसर्च का यह अनुमान 41 अग्रणी संकेतकों के समूह पर आधारित समग्र सूचकांक पर आधारित है।

घोष ने कहा कि यह अनुमान दर्शाता है कि जून और सितंबर के बीच आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती रही लेकिन अक्टूबर में आर्थिक गतिविधियों के सुधरने से तीसरी तिमाही में आंकड़े बेहतर होने की उम्मीद बंधती है। उन्होंने कहा कि कई संकेतक वैश्विक झटकों, मुद्रास्फीति-जनित दबावों और बाहरी मांग में कमी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के जुझारू चरित्र को दर्शाते हैं।

विस्तार-एयर इंडिया विलय से एसआईए का वित्तीय बोझ 'न्यूनतम' रहेगा

25.1 प्रतिशत हिस्सेदारी लेगी

नयी दिल्ली। एजेंसी

विस्तार-एयर इंडिया के प्रस्तावित विलय सौदे का सिंगापुर एयरलाइंस ग्रुप (एसआईए) पर वित्तीय बोझ 'न्यूनतम' रहेगा। सिंगापुर एयरलाइंस विस्तारित एयर इंडिया में 25.1 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने जा रही है। कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजारों को यह जानकारी दी। एसआईए ने लगभग 50 साल पहले भारत में सेवाएं शुरू की थी। उसे जल्द ऐसी एयरलाइन में हिस्सेदारी मिलने की उम्मीद है जो विलय के बाद उसकी तुलना में चार से पांच गुना बड़ी होगी। नियामकीय मंजूरी मिलने के बाद यह सौदा 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। टाटा समूह और एसआईए ने मंगलवार को विस्तार के एयर इंडिया के साथ विलय की घोषणा की थी।

विलय के लिए एसआईए समूह का वित्तीय बोझ विस्तार में उसकी 49 प्रतिशत हिस्सेदारी के कुल मूल्य के बराबर होगा। यह करीब 2,058.5 करोड़ रुपये नकद बैठेगा। वर्तमान में विस्तार में एसआईए की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है और बाकी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी टाटा समूह के पास है। विलय सौदे के बाद, एसआईए की एयर इंडिया में 25.1 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। सूचना में कहा गया है कि प्रस्तावित विलय के तहत यह देखते हुए कि एसआईए विस्तारित एयर इंडिया में 25.1 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने जा रही है, उसपर वित्तीय बोझ काफी कम रहेगा। सौदे के बारे में भेजी सूचना में एसआईए ने कहा कि इस विलय से समूह को मजबूत समर्थन और वित्तीय स्थिति वाले मंच पर न्यूनतम वित्तीय खर्च से बड़ा अवसर मिलेगा। एसआईए का इरादा एयर इंडिया में निवेश का पूरा वित्तपोषण अपने आंतरिक संसाधनों से करने का है।

त्योहारों के दौरान नियुक्ति गतिविधियां 73 प्रतिशत बढ़ीः रिपोर्ट

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

इस साल त्योहारों के दौरान अगस्त-अक्टूबर अवधि में नियुक्ति गतिविधियां पिछले साल के मुकाबले 73 प्रतिशत बढ़ी हैं। ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक, खुदरा तथा बैंक, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र (बीएफएसआई) की अगुवाई में नियुक्तियां बढ़ी हैं। व्यापार सेवाएं उपलब्ध कराने वाली क्वेस कॉर्प के आंकड़ों के अनुसार, इस दौरान 1,00,000 ऑर्डर के साथ मांग बढ़ने से ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक, खुदरा तथा बैंक, वित्तीय सेवाएं और बीमा क्षेत्रों में नियुक्ति गतिविधियां बढ़ीं। त्योहारों के दौरान मांग पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले बेहतर रही है। यह अर्थव्यवस्था में वृद्धि का संकेत है। क्वेस स्टाफिंग के सीईओ (मुख्य कार्यपालक अधिकारी) नितिन दवे ने कहा, "महामारी संकट के बाद से अर्थव्यवस्था में पुनरूद्धार जारी है। इसके साथ ई-कॉमर्स और खुदरा क्षेत्रों में नियुक्ति गतिविधियां बढ़ी हैं...।" उन्होंने कहा कि होटल, वाहन, दूरसंचार क्षेत्रों में भी तेजी देखी जा रही है। ऐसे में इन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से काम करने वालों की काफी जरूरत है।"

बिजली खंभों, ट्रैफिक सिग्नल पर 5जी के छोटे उपकरण लगाने की सिफारिश

नयी दिल्ली। एजेंसी

दूरसंचार नियामक ट्राई ने बिजली के खंभों, बस स्टॉप और ट्रैफिक सिग्नल पर 5जी सेवाओं के छोटे उपकरण लगाने की सिफारिश करने के साथ ही छोटे दूरसंचार उपकरण लगाने के लिए मंजूरी लेने की जरूरत खत्म करने का सुझाव दिया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मंगलवार को जारी अपनी अनुशंसा में कहा कि दूरसंचार विभाग को 600 वॉट से कम विकिरण क्षमता वाले 'लो पावर बेस ट्रांसीवर स्टेशन' (एलपीबीटीएस) लगाने की मंजूरी लेने की बाध्यता से मुक्त किया जाना चाहिए।

5जी के स्पेक्ट्रम बैंड 2जी, 3जी एवं 4जी नेटवर्क की तुलना में बहुत कम इलाके को कवर करते हैं। इसकी वजह से 5जी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और सिग्नल अंतराल को दूर करने के लिए कम क्षमता वाले दूरसंचार उपकरण लगाने की जरूरत पड़ेगी। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए ट्राई ने दूरसंचार विभाग को सुझाव दिया है कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम में संशोधन कर बिजली खंभे, बस स्टॉप एवं ट्रैफिक सिग्नल जैसे 'स्ट्रीट फर्नीचर' को भी शामिल किया जाए। इसके लिए ट्राई ने जरूरी अधिसूचना जारी करने को भी कहा है। विकिरण का कम स्तर होने से छोटे दूरसंचार उपकरणों को अधिक सुरक्षा की जरूरत नहीं होगी और उन्हें लगाने में भी अधिक समस्या नहीं होगी। इन उपकरणों को सड़कों के किनारे के बिजली खंभों, बस स्टॉप और ट्रैफिक सिग्नल पर भी आसानी से लगाया जा सकता है।

एक दिसंबर से बदल जाएंगे ये नियम, जानें किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी?

नई दिल्ली।एजेंसी

दिसंबर महीना शुरू होने वाला है। हम जानते हैं कि हर महीना अपने साथ कुछ नए बदलाव लेकर आता हैं। ऐसे में दिसंबर महीने की शुरुआत के साथ भी कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। इन परिवर्तनों का असर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा, ऐसे में इनकी जानकारी जरूरी है।

एलपीजी-सीएनजी व पीएनजी की कीमतों में भी हो सकता है बदलाव

पिछले महीने की शुरुआत में कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतें घटी थी, पर घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। ऐसे में, उम्मीद है कि रसोई गैस के सिलेंडर इस बार एक दिसंबर से सस्ते हो सकते हैं। अक्तूबर महीने के आंकड़ों में खुदरा महंगाई दर में नरमी के संकेत मिले हैं। इसके बाद इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि इस महीने के अंत में पेट्रोलियम कंपनियां रसोई गैस की कीमतों में भी बदलाव की घोषणा कर सकती हैं। हालांकि ऐसा होगा या नहीं यह एक दिसंबर की सुबह तक ही साफ हो पाएगा। इसके अलावा सीएनजी व पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव की घोषणा हो सकती है।

एटीएम से नकद निकालने का तरीका बदलेगा

दिसंबर महीने से एटीएम से पैसे निकालने का तरीका भी बदल सकता है। वर्तमान में हम जिस तरीका का इस्तेमाल कर एटीएम से नकद निकालते हैं, उसमें कई बार फर्जीवाडा होने की आशंका बनी रहती है। जानकारी के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक दिसंबर महीने में एटीएम से कैश निकालने की प्रक्रिया में बदलाव कर सकते हैं। बताया गया है कि एक दिसंबर के बाद से एटीएम में कार्ड लगाते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जेनरेट होगा। इस ओटीपी की एटीएम स्क्रीन पर दिए गए कॉलम में प्रविष्टि करने के बाद

ही नकद बाहर निकलेगा।

ट्रेनों की समय-सारणी बदलेगी

दिसंबर महीने में देश के अधिकतर हिस्सों में सर्दियां बढ़ने लगती है। सर्दियों के साथ कोहरा बढ़ने लगता है। इससे ट्रेनों के आवागमन में परेशानी होने लगती है। नतीजतन, रेलवे को कई ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला करना पड़ता है। कुहासे को देखते हुए रेलवे अपनी समय सारणी में भी बदलाव करती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि रेलवे दिसंबर महीने में रेलवे की समय सारणी संशोधित करेगी और नई समय-सारणी के अनुसार ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।

पेंशनर्स नहीं जमा कर पाएंगे लाइफ सर्टिफिकेट

पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण-पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2022 है। ऐसे में अगर इस महीने के अंत तक उन्होंने अपना जीवन प्रमाण-पत्र जमा नहीं किया तो एक दिसंबर से ऐसा करने में उन्हें असुविधा हो सकती है। अगर समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया गया तो उनकी पेंशन रुक भी सकती है।

बैंकों में 13 दिन नहीं होगा कामकाज

दिसंबर महीने में कुल 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में दूसरे और चौथे शनिवार और रविवार की छुट्टियां शामिल हैं। इस महीने में क्रिसमस, वर्ष का आखिरी दिन (31 दिसंबर) और गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती भी है। इन अवसरों पर भी बैंकों में छुट्टी रहेगी। स्थानीय पर्व-त्योहारों के आधार पर भी कई राज्यों में छुट्टियां हैं। छुट्टी के दिनों में बैंकों में कामकाज बंद रहेगा। हालांकि, इस दौरान ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए ग्राहक अपना काम निपटा सकेंगे।

जुर्माने के साथ भर सकेंगे वित्तीय वर्ष 2021-22 का आयकर रिटर्न

अगर आपने 2021-22 का आयकर रिटर्न अब तक दाखिल नहीं किया है तो जुर्माने के साथ इसे 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है तो आपको 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा। कुल आय पांच लाख रुपये से ज्यादा होने पर जुर्माने की रकम बढ़कर 5,000 रुपये हो जाएगी।

अग्रिम कर की तीसरी किस्त 15 दिसंबर तक जमा की जा सकेगी

2022-23 के अग्रिम कर (एडवांस टैक्स) की तीसरी किस्त भरने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है। जिनका सालाना आयकर 10,000 रुपये से ज्यादा होता है, उन्हें अग्रिम कर जमा करना पड़ता है। अगर 15 दिसंबर तक वे 75 फीसदी कर पहले जमा नहीं करते हैं या कम कर जमा करते हैं तो एक फीसदी ब्याज लगेगा।

रिटर्न दाखिल करने में हुई है गलती तो 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं

हो सकता है कि आपने वित्त वर्ष 2021-22 का आयकर रिटर्न भर दिया हो और उसमें कोई चूक हो गई हो। ऐसे में आप 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद गलती नहीं सुधार पाएंगे। इसकी वजह से आपके पास आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है।

सिर्फ जिंदगी नहीं GDP को झटका देती हैं सड़क दुर्घटनाएं

नई दिल्ली। एजेंसी

सड़क पर हो रहे हादसे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। जो सड़क देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती हैं, वहां होने वाले हादसे उसी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। इन हादसों में जान गंवाने वाले लोगों से न केवल अपनों को दुख पहुंचता है, बल्कि देश की डीजीपी को भी झटका लगता है। रोड सेफ्टी के मानकों का पालन कर हम न केवल अपनी जान बचा सकते हैं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान जारी रख सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा सड़क हादसे ओवर स्पीड के कारण ही होती है और सबसे ज्यादा दुर्घटना का शिकार बाइक सवार होते हैं।

ट्रैफिक नियमों का अगर सही से पालन कर लें तो हम न केवल खुद को बल्कि देश की इकोनॉमी को भी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो जो सड़क किसी भी देश की तरक्की का आधार हैं, उसपर होने वाले हादसे उसकी अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत में होने वाले सड़क हादसों की लागत 5.96 लाख करोड़ रुपए थी, जो उसकी जीडीपी का 3.14

प्रतिशत हिस्सा था। वहीं वाहन कलपुर्जे बनाने वाली कंपनी बॉश ने साल 2021 में जारी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं के चलते होने वाले कुल सामाजिक-आर्थिक नुकसान की रकम 15.71 से 38.81 अरब डॉलर तक है। ये नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को झटका देते है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक साल 2018 में ओवर स्पीड के कारण हर साल 6 लाख 38 हजार से अधिक हादसे ओवरस्पीड के कारण होते रहे। वहीं 65 हजार से अधिक हादसे आकस्मित कारणों से होते है। जबकि वहीं गलत दिशा में ड्राइविंग के कारण 53 हजार से अधिक हादसे होते हैं। वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण 26 हजार से अधिक हादसे होते रहे। रेड लाइट जंप करने के कारण हर साल 10 हजार से अधिक हादसे हो जाते हैं। सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या के आधार पर बात करें तो साल 2014 के मुकाबले 2018 सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या में गिरावट आई है। साल 2014 में सड़क दुर्घटना के कारण 7 हजार से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। ये आंकड़ा साल 2018 में गिरकर 4200 के करीब पहुंच गया है। सड़क सुरक्षा मानकों में सुधार और ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर लगातार हो रही सख्ती के कारण सड़क हादसे में होने वाली मौत में भारी गिरावट राहत की खबर है।

अगर कैटेगरी की बात करें तो सड़क दुर्घटना का सबसे ज्यादा शिकार बाइकर्स होते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर साझा की गई जानकारी के मुताबिक टू व्हीलर्स से होने वाले हादसों का प्रतिशत 43.5 फीसदी है। वहीं 17.8 फीसदी हादसे पैदल चलने वाले लोगों के साथ हुए हैं। ऑटो रिक्शा से होने वाले हादसों की संख्या 3.9 फीसदी है। जबकि 3.2 फीसदी हादसे साइकिल सवारों के साथ हुए है। कार, टैक्सी से होने वाले सड़क हादसों का प्रतिशत करीब 14 फीसदी है तो सबसे कम सड़क हादसे बसों के साथ होते हैं। इनका प्रतिशत 2.3 फीसदी है। बाइक सवार अगर अपनी रफ्तार पर लगाम रखें और हेलमेट पहनकर तक सड़क पर निकले तो इन आंकड़ों को आसानी से कम किया जा सकता है।

टाटा प्ले ने टीवी पैक्स में संशोधन कर दर्शकों के लिए मनोरंजन को ज्यादा किफायती बनाया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

आर्थिक मंदी और घटती आय के वातावरण में टाटा प्ले ने उपभोक्ताओं के टीवी पैक्स में स्वेच्छा से संशोधन करने की योजना बनाई है, और कुछ संग्रहों से कुछ चैनल हटाने और कुछ पैक्स के मूल्य कम करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय टाटा प्ले ने दर्शकों द्वारा मनोरंजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को देखते हुए लिया क्योंकि घटती आय के कारण कुछ दर्शक गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं।

इस अभियान के बारे में टाटा प्ले के प्रवक्ता ने कहा, ''टाटा प्ले अपने ग्राहकों को सस्ते दाम में उनके मन पसंद पैक उपलब्ध कराने के लिए बध्य है। इसी कोशिश में हमने अपने कुछ पैक के दाम कम किए हैं और इसके चलते कुछ चैनल भी हटाए हैं। जो ग्राहक इन चैनल को अपने पैक में वापस सम्मिलित करना चाहते हैं वो टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल दे के कर सकते हैं।''

टाटा प्ले को उम्मीद है कि इस कदम से उपभोक्ताओं की अस्थिरता में कमी आएगी, और वो किफायती मूल्यों में टीवी देखने का बेहतरीन अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। टाटा प्ले ने हाल ही में अपने सुपर सेवर पैक पेश किए हैं ताकि उपभोक्ताओं के टीवी के शुल्क में कमी लाने में मदद मिले और मनोरंजन सभी के लिए ज्यादा उपलब्ध व किफायती बन सके। यह अभियान दिसंबर से शुरू कर दिया जाएगा।

ये लोग भूलकर भी लगाएं लाल तिलक, वरना बढ़ सकती है मुसीबतें

हिंदू धर्म में माथे पर तिलक लगाने का खास महत्व होता है. हिंदू धर्म की मान्यता है कि माथे पर तिलक लगाने से व्यक्ति के अन्दर सकारात्मकता आती है और कुंडली में मौजूद उग्र ग्रह शांत होते हैं. शुभ या मांगलिक अवसरों पर, विशेष पर्व या त्योहारों पर सामान्यतः लाल तिलक लगाया जाता है. तिलक लगाने से व्यक्तित्व में सात्विकता झलकती है, लेकिन लाल रंग का तिलक इस इस राशि के लोगों को भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए?

श्री रघुनंदन जी
9009369396
ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुविद अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन द्वारा गोल्ड मेडलिस्ट

क्यों नहीं लगाना चाहिए लाल तिलक?

ज्योतिष में रंगों का संबंध ग्रहों से बताया गया है. हमारे जीवन में सुख –दुख का प्रभाव ग्रहों के राशि परिवर्तन और चाल परिवर्तन पर भी निर्भर करता है. इसके साथ ही ग्रहों से संबंधित रंगों का प्रभाव भी व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है. ज्योतिष के मुताबिक, लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से है. लाल रंग को सबसे शक्तिशाली रंग माना जाता है. ज्योतिष में मंगल को साहस और पराक्रम का ग्रह माना गया है. इन्हें क्रूर ग्रह कहा गया. मंगल की तरह लाल रंग भी उत्तेजना और क्रोध का प्रतिनिधि करता है.

इन्हें नहीं लगाना चाहिए लाल रंग का तिलक

ज्योतिष शास्त्र में मंगल को मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह माना गया है. ग्रहों का प्रभाव उनके स्वामित्व वाली राशियों पर सबसे अधिक पड़ता हैं. मंगल ग्रह का रंग लाल है, इनके लिए लाल रंग बेहद शुभ माना जाता है. ऐसे में मेष और वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में मंगल नीच और अशुभ भाव में हों तो इन जातकों में उत्तेजना और क्रोध की वृद्धि होती है. ऐसे लोगों के लिए लाल रंग शुभ नहीं होता है. इन लोगों को लाल रंग अशुभ फल प्रदान करता है. इसलिए इन्हें लाल रंग से बचना चाहिए. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इन स्थिति में मेष और वृश्चिक राशि के जातकों को लाल रंग का तिलक नहीं लगाना चाहिए.

लाल रंग से शनि देव होते है नाराज

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि और मंगल ग्रह में शत्रुता का भाव रहता है. वहीं शनि को काला रंग प्रिय है जबकि शनि को लाल रंग से नफरत है. ऐसे में शनि के स्वामित्व वाली राशियों मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए लाल रंग अशुभ माना जाता है.

साल 2023 के पहले दिन करें ये उपाय, सालभर बरसेगा पैसा

नववर्ष शुरू होने में कुछ दिन बाकी हैं। हर शख्स चाहता है कि उसका साल अच्छे से गुजरे। सालभर धन की देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। देवी-देवताओं की कृपा से खूब तरक्की मिले। सभी जातक चाहते है कि आने वाला वर्ष सुख-सुविधाओं से भरा रहे। इसके लिए लाल किताब में कुछ उपायों के बारे में बताया गया है। इन ज्योतिष उपायों से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं न्यू ईयर के पहले दिन किन उपायों को करने से लाभ होगा।

गर्म वस्त्रों का दान करें

नए साल के पहले दिन जरूरतमंदों को कंबल दान करें। ऐसा करने से घर में खुशियों का आगमन होता है।

काला सुरमा लगाएं

नए साल के पहले दिन आंखों में काला सुरमा लगाएं। इससे दोष और डर से छुटकारा मिलता है। साथ ही कुंडली में कमजोर ग्रहों की स्थिति में सुधार होता है।

नारियल का चमत्कारी उपाय

वैदिक ज्योतिष के अनुसार नारियल का उपाय व्यक्ति को बुरी नजर से बचाता है। नए साल के पहले मंगलवार, गुरुवार या शनिवार के दिन एक नारियल अपने और परिवार के सदस्यों पर 21 बार वार दें। फिर इस नारियल को पानी में बहा दें। ऐसा करने से जातक को बुरी नजर के साथ दोष से निजात मिलता है।

हनुमानजी को चोला चढ़ाएं

नव वर्ष के पहले दिन पवनपुत्र की पूजा का महत्व है। इस दिन बजरंगबली की पूजा करने के साथ चोला चढ़ाएं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार साल में दो बार चोला अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं।

वास्तु के इस उपाय से पैसों से कभी नहीं खाली रहेगा आपका पर्स, बस कर लें ये उपाय

धन की जरूरत हर किसी को होती है क्योंकि धन से सभी आवश्कताओं की पूर्ति होती है. धन के बिना जीवन चलना असंभव होता है। हर कोई यह चाहता है कि वह अपने जीवन में जल्दी से जल्दी और ज्यादा धन एकत्रित करें. ताकि जीवन में धन का अभाव न हो। कई लोग धन अर्जित करने के लिए खूब मेहनत करते हैं ताकी उनके जिंदगी में किसी भी तरह की कमी का सामना न करना पड़े. वहीं, कई लोग अपने जीवन में खूब सारा धन कमा भी लेते हैं लेकिन वह उस धन को बचा पाने में असफल ही रहते हैं. इस समस्या के पीछे वास्तु दोष एक बड़ा कारण हो सकता है. वास्तु दोष को खत्म करने के लिए कई तरह के उपाय भी होते हैं, जिसे अपनाने से इससे छुटकारा मिलता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति अपने पर्स में पैसे के साथ कुछ ऐसी चीजे भी रखी तो उसे अपने जीवन में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती. आइए जानते हैं अगर कोई व्यक्ति अपने बटुए में कौन-कौन सी चीजें रखें.

मां लक्ष्मी की फोटो

शास्त्रों में मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है. मान्यता है कि जिन लोगों पर मां लक्ष्मी मेहरबान हो जाए तो उनके जीवन में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती. मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अपने पर्स में माता लक्ष्मी की बैठी हुई मुद्रा में एक छोटी से तस्वीर अवश्य रखें.

चावल के दाने

चावल के दाने को अक्षत भी कहा जाता है. हिंदू धर्म में चावल के दाने को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है. अगर कोई व्यक्ति बहुत पैसे कमाते है लेकिन उसका पैसा किसी न किसा बहाने से खर्च हो जाता है तो अपने पर्स में चावल के दाने अवश्य रखें. इस उपाय से बिना वजह के आपके खर्चे रूक जाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में लगातार इजाफा होता जाएगा.

सोने-चांदी के सिक्के

सोने -चांदी के सिक्के को शुभता और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है. वास्तु के अनुसार अगर सोने-चांदी के सिक्के के कुछ उपाय किए जाए तो धन की समस्या नहीं आती है. जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन कमाने और बचत करने के लिए सोने-चांदी के सिक्के को सबसे पहले मां लक्ष्मी की चरणों के पास कुछ दिन रख लें फिर शुक्रवार के दिन उसे उठाकर अपने पर्स में रखें. इस उपाय से आपके जीवन में हमेशा सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

लाल कपड़ा या कागज

अगर आप यह चाहते है कि आपका पर्स पैसों से कभी खाली न रहें तो इसके लिए लाल कपड़े का उपाय कर सकते हैं. वास्तु के अनुसार पर्स में लाल रंग के कपड़े या फिर कागज को अपने पर्स में जरूर रखें. लाल रंग मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है.

संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

गोमती चक्र

गोमती चक्र जीवन में सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. मां लक्ष्मी की प्रसन्न करने में इसका विशेष उपयोग किया जाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार मां लक्ष्मी की कृपा के लिए यह काफी शुभ माना जाता है. मां लक्ष्मी के चरणों में गोमती चक्र को अर्पित करके इसे पर्स में रखने से कभी पैसों की किल्लत नहीं होती है.

अगहन महीने में सूर्य पूजा का महत्व

रविवार को उगते हुए सूरज को जल चढ़ाने से दूर होती है बीमारियां, उम्र भी बढ़ती है

अगहन महीने का शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है। जो कि 8 दिसंबर तक रहेगा। इस मार्गशीर्ष महीने में भगवान सूर्य की पूजा का भी विशेष फल बताया गया है। ग्रंथों में कहा गया है कि इस महीने रविवार को उगते हुए सूरज को जल चढ़ाने से हर तरह के दोष और पाप खत्म हो जाते हैं।

अगहन महीने में रविवार को बिना नमक खाए व्रत करने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। ऐसा करने से कुंडली में ग्रह-नक्षत्रों के अशुभ फल में कमी आती है। 27 नवंबर को मार्गशीर्ष महीने का रविवार रहेगा।

धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि मार्गशीर्ष महीने में सूर्योदय से पहले उठकर नहाना सेहत के लिए अच्छा होता है। इस महीने में सूर्योदय के वक्त सूर्य को जल चढ़ाने से हर तरह के रोग खत्म होने लगते हैं और उम्र भी बढ़ती है। वहीं, आयुर्वेद के जानकारों का कहना है कि सूर्योदय के वक्त सूर्य नमस्कार करने से हर तरह की बीमारियां दूर होती हैं।

कैसे चढ़ाएं जल, किन बातों का ध्यान रखें

तांबे के लोटे में जल भरें और ऊँ सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य को चढ़ने वाला जल किसी चौड़े बर्तन में गिरे। जमीन पर न गिरे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद कुछ देर सूर्य के सामने बैठकर ऊँ आदित्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। भगवान सूर्य को चढ़ाए हुए जल को तांबे के किसी बर्तन में इकट्?ठा करने के बाद मदार के पेड़ में चढ़ा दें। मदार में जल न चढ़ा पाएं तो तुलसी या ऐसे पौधे में चढ़ा दें जहां वो जल किसी के पैरों में न आएं।

रविवार को किन चीजों का दान करें

अगहन महीने के दौरान शीत ऋतु के चलते ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद लोगों को रविवार के दिन गेहूं, गुड़, ऊनी कपड़े और कंबल का दान करना चाहिए। इस महीने के रविवार को अनाज और अन्य खाने की चीजों के दान का विधान बताया गया है। साथ ही किसी गौशाला में घास और कुछ पैसे का दान करें।

चार ग्रहों का संयोगः सूर्य, बुध और शुक्र एक ही नक्षत्र में, इस कारण मौसम में अचानक बदलाव और राजनीतिक विवाद होने के योग हैं

इस महीने वृश्चिक राशि में पहले बुध, फिर शुक्र और उसके बाद सूर्य ने प्रवेश किया है। मौजूदा स्थिति में ये तीनों ग्रह एकसाथ मंगल की राशि और शनि के अनुराधा नक्षत्र में है। इनके सामने यानी वृष राशि में मंगल है। जो कि अपने ही नक्षत्र मृगशिरा में है। इस तरह इन चार ग्रहों का संयोग बन रहा है।

चार ग्रहों का असर- शनि के नक्षत्र में इन ग्रहों के होने से देश में कई जगहों पर अचानक ठंड बढ़ सकती है। जिससे कुछ नुकसान होने की आशंका भी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने से हवा में ठंडक बढ़ेगी। लौहे से बनी चीजों में तेजी आ सकती है। मंगल के साथ दृष्टि संबंध बनने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ने की आशंका है। जिससे कुछ देशों में अशांति का माहौल बन सकता है।

मंगल के कारण आपदाओं की आशंका- मंगल के अपने ही नक्षत्र में होने से सेना नायक, रक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए उन्नति वाला समय हो सकता है। लेकिन प्राकृतिक प्रकोप और कुछ बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। संक्रमण बढ़ने के भी आशंका रहेगी। लाल वस्तुओं के भाव बढ़ेंगे। मौजूदा ग्रहों की स्थितियां मौसम में भी उतार-चढ़ाव लाएंगी। लोगों को अपने काम पूरे करने के लिए भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ सकती है। राजनीतिक विवाद बढ़ सकते हैं। आरोप-प्रत्यारोप भी होंगे।

देश की सबसे छोटी ई-कार लॉन्च, कीमत 5 लाख से भी कम, सिंगल चार्ज में जाएगी 200 किमी

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप PMV Electric ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी है। इस कार को ईएएस-ई (EaS-E) नाम दिया गया है। खास बात यह है कि यह देश की सबसे छोटी और सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार (Cheapest Elecetric Car in India) बन गई है। पीएमवी इलेक्ट्रिक ने ईएएस-ई को 4.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। हालांकि, यह कीमत पहले 10,000 ग्राहकों के लिए है। इसके बाद कंपनी इसकी कीमत बढ़ा सकती है।

दिलचस्प बात यह है कि PMV Eas-E का वर्तमान में भारत में EV सेगमेंट में अभी तक कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। हालांकि, यह एमजी मोटर की अपकमिंग एयर ईवी को टक्कर देगी। जिसे अगले अगले साल 5 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने आधिकारिक लॉन्च से पहले ही ईवी के लिए लगभग 6,000 बुकिंग हासिल कर ली है। इस इलेक्ट्रिक कार को PMV की ऑफिशियल वेबसाइट से महज 2,000 रुपये में बुक किया जा सकता है।

कितने सीटर है कार?

PMV EaS-E देश में खरीदी जा सकने वाली सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार है। इसमें एक बार में दो एडल्ट और एक बच्चा बैठ सकता है। कार के साफ तौर पर शहर में इस्तेमाल करने के लिए हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसकी लंबाई 2,915 मिमी, चौड़ाई 1,157 मिमी और ऊंचाई 1,600 मिमी है। कार का व्हीलबेस 2,087 मिमी का है, जबकि ग्राउंड क्लीयरेंस 170 मिमी है. साथ ही, ई का कर्ब वेट लगभग 550 किलोग्राम है।

कितने सीटर है कार?

PMV EaS-E देश में खरीदी जा सकने वाली सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार है। इसमें एक बार में दो एडल्ट और एक बच्चा बैठ सकता है। कार के साफ तौर पर शहर में इस्तेमाल करने के लिए हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसकी लंबाई 2,915 मिमी, चौड़ाई 1,157 मिमी और ऊंचाई 1,600 मिमी है। कार का व्हीलबेस 2,087 मिमी का है, जबकि ग्राउंड क्लीयरेंस 170 मिमी है. साथ ही, EV का कर्ब वेट लगभग 550 किलोग्राम है।

कितनी है कार की टॉप स्पीड?

जहां तक लुक्स की बात है, PMV EaS-E सर्क्युलर हेडलैम्प्स के साथ काफी फंकी दिखती है। इसमें एलईडी लाइट, स्लिम एलईडी लैंप और होरिजोंटल टेलगेट देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक कार के पावर आउटपुट की बात करें तो इसमें 13 hp की की पावर और 50 Nm का पीक टॉर्क मिल जाएगा। यह 70 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड से चल सकती है और केवल 5 सेकंड के भीतर 0 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है।

कितनी मिलेगी रेंज?

पीएमवी ईएएस-ई माइक्रो इलेक्ट्रिक कार में 3 टाइप की बैटरी पैक का ऑप्शन का मिल जाता है. यह एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर तक चल सकती है। कंपनी का दावा है कि इसकी सबसे कम रेंज 120 किलोमीटर के करीब होगी। यह चार घंटे से अधिक समय में पूरी तरह से रिचार्ज हो सकती है. माइक्रो कार को किसी भी 15 के चार्जर से चार्ज किया जा सकता है. कंपनी कार के साथ 3 के का एसी चार्जर भी दे रही है।

ड्यूरोप्लाई के विनियर्स और प्लाईवुड की प्रीमियम रेंज की सराहना

आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर्स इंडिया डिज़ाइन डिबेट में शामिल हुए आर्किटेक्ट्स

भोपाल। आईपीटी नेटवर्क

ड्यूरोप्लाई के विनियर्स और प्लाईवुड की प्रीमियम रेंज को भोपाल के आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स और डिज़ाइन थिंकर्स ने काफी सराहना की है । आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर्स इंडिया मैगज़ीन द्वारा भोपाल में हाल ही में आयोजित आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर्स इंडिया डिज़ाइन डिबेट में ड्यूरोप्लाई के प्रतिनिधियों ने समूचे भारत के एकत्रित हुए आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स को ड्यूरोप्लाई के प्रीमियम रेंज के प्रोडक्ट्स प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में श्री लक्ष्मेंद्र माहेश्वरी, ब्रांच हेड - भोपाल,

ड्यूरोप्लाई, ने कहा, 'यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारी प्रोडक्ट रेंज को आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइन कम्युनिटी के एक विशेष समूह द्वारा सराहना प्राप्त हुई है। ग्राहकों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को जानकार दर्शकों द्वारा विशेष रूप से पसंद किया गया, जो हमें इंडस्ट्री के लिए अग्रणी प्रोडक्ट्स की पेशकश करने हेतु प्रेरित करते हैं।'

श्री लक्ष्मेंद्र माहेश्वरी ने उपस्थित कम्युनिटी को ड्यूरोप्लाई प्रोडक्ट्स की विशेषताओं के बारे में बताते हुए कहा कि ड्यूरोप्लाई में इनोवेशन एक विचारशील मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को गति प्रदान करती है जिससे हमारी कंपनी लगातार प्रोडक्ट्स की एक प्रीमियम रेंज सुनिश्चित करती है।

ड्यूरोप्लाई, 65 वर्षों से अधिक समय से इंडस्ट्री के लिए प्लाईवुड, ब्लॉकबोर्ड्स, दरवाजे और अन्य संबंधित प्रोडक्ट्स की प्रीमियम रेंज की पेशकश कर रहा है। मौजूदा कंपनियों की तुलना में यह अपने क्षेत्र का सबसे पुराना और सबसे अनुभवी खिलाड़ी है और इंडस्ट्री की गहन समझ के साथ ही नवीनतम प्रोडक्ट्स की पेशकश करने के रूप में विशेष पहचान रखता है।

अवांछित एसएमएस, कॉल रोकने की प्रौद्योगिकी पर काम जारीः ट्राई

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए अन्य नियामकों के साथ एक संयुक्त कार्ययोजना पर काम कर है। इसके तहत लोगों को अवांछित कॉल और संदेशों (एसएमएस) का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर काम किया जा रहा है। ट्राई ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि अनपेक्षित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) या अवांछित कॉल, एसएमएस जनता के लिए असुविधा का एक प्रमुख स्रोत हैं और यह व्यक्तियों की गोपनीयता को प्रभावित करता है। दूरसंचार नियामक ने कहा, ''अब ऐसी गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटिंग इकाइयों (यूटीएम) के खिलाफ शिकायतें दर्ज की जाती हैं, जिनके मामले में यूसीसी एसएमएस में उछाल देखा गया है। साथ ही यूसीसी कॉल भी उन चिंताओं में से एक हैं जिनसे यूसीसी एसएमएस के साथ समान रूप से निपटने की आवश्यकता है।'' बयान के अनुसार, ''ट्राई कई हितधारकों के साथ मिलकर यूटीएम से भी यूसीसी की जांच के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। इनमें कृत्रिम मेधा (एआई) का उपयोग करते हुए यूसीसी का पता लगाने की प्रणाली का कार्यान्वयन जैसे कदम शामिल है।'' गौरतलब है कि ट्राई ने अवांछित एसएमएस और कॉल को रोकने के लिए दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक प्राथमिकता विनियम, 2018 भी जारी किया था।

जीईएम पोर्टल से सार्वजनिक खरीद एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हुई

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकारी खरीद पोर्टल जीईएम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद चालू वित्त वर्ष में अब तक एक लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गई है। इसकी वजह विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की खरीद गतिविधियों में हुई वृद्धि है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए नौ अगस्त, 2016 को गवर्नमेंट ई-मार्केट (जीईएम) पोर्टल शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि जीईएम पोर्टल देश के लिए उद्यमिता उत्साह दर्शाने और पारदर्शिता की दृष्टि से 'पासा पलटने' वाला है। मोदी ने एक ट्वीट में कहा, ''बहुत अच्छी खबर। भारत के उद्यमिता उत्साह और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए जीईएम पासा पलटने वाला है। इस मंच पर अपने उत्पाद प्रदर्शित करने वालों की मैं सराहना करता हूं और दूसरों से भी ऐसा करने को कहता हूं।'' इससे पहले वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जीईएम मंच से खरीद के आंकड़े साझा किए। जीईएम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पी के सिंह ने कहा कि मौजूदा रुझान को देखते हुए इस वित्त वर्ष के अंत तक यह आंकड़ा 1.80 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''आज हमने एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर लिया। चालू वित्त वर्ष के लिए हमारा लक्ष्य 1.5 लाख करोड़ रुपये का था लेकिन मौजूदा रुख को देखते हुए हम 1.80 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकते हैं।'' इस पोर्टल से खरीदारी करने वाले शीर्ष पांच राज्यों में गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल हैं।

कमजोर रुपये का सामना करने में अधिकांश भारतीय कंपनियां सक्षमः मूडीज

नयी दिल्ली। एजेंसी

मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने मंगलवार को कहा कि भारत में अधिकांश कंपनियां कमजोर रुपये का सामना कर सकती हैं लेकिन विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती ब्याज दरों और ऊंची ऊर्जा कीमतों से रुपये में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।

मूडीज ने भारत में गैर-वित्तीय कंपनियों के बारे में की गई एक टिप्पणी में कहा कि साल की शुरुआत से रुपये में करीब 10 प्रतिशत तक अवमूल्यन होने के बाद भारतीय मुद्रा 25 नवंबर को 81.67 प्रति डॉलर के भाव पर

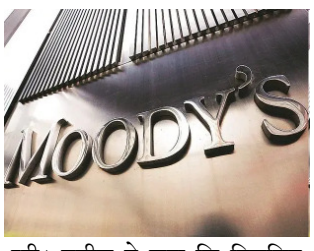

रही। मूडीज ने कहा कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज दरों में लगातार हो रही वृद्धि और ऊर्जा कीमतों के बढ़ने से चालू खाते का घाटा बढ़ा है जिससे रुपये पर दबाव बढ़ गया है। उसने कहा, ''इन बाहरी घटकों से रुपये में उतार-चढ़ाव बढ़ता है लेकिन भारत में रेटिंग वाली अधिकांश कंपनियों के पास रुपये की घटती कीमत से निपटने के लिए संसाधन मौजूद हैं।'' मूडीज ने कहा कि रुपया कमजोर होने से उन कंपनियों पर अधिक असर पड़ेगा जिनकी लागत डॉलर में आती है जबकि राजस्व सृजन रुपये में होता है। लेकिन रेटिंग वाली कंपनियों पर नकारात्मक क्रेडिट का असर सीमित या अस्थायी रहने की उम्मीद है।

क्यों नहीं मिल रहा अमूल का मक्खन? कंपनी के एमडी ने बताई असली वजह

नई दिल्ली। एजेंसी

देश के कई राज्यों में अमूल मक्खन की कमी की बातें सामने आ रही है। दुकानों में यह मक्खन नहीं मिल रहा है और लोगों को दूसरे विकल्पों का सहारा लेना पड़ रहा है। अमूल ब्रांड के प्रॉडक्ट्स की मार्केटिंग करने वाली कंपनी गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के एमडी आर एस सोढ़ी ने इसकी वजह बताई है। उन्होंने कहा कि इस बार दिवाली में मक्खन की जबरदस्त मांग रही। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसका अनुमान नहीं लगाया था। इस कारण टेम्परारी शॉर्टेज हो गई थी। लेकिन इसके बाद पैनिक बाइंग के कारण स्थिति और बदतर हो गई। उन्होंने कहा कि कंपनी ने प्रॉडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है।

बिजनस स्टैंडर्ड में छपी एक खबर के मुताबिक सोढ़ी ने कहा कि दिवाली में मांग उम्मीद से कहीं ज्यादा रही। इस वजह से मक्खन की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। कंपनी ने प्रॉडक्शन बढ़ा दिया है और अगले कुछ दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी। एंपी के मुताबिक भारत में बटर मार्केट 6.86 अरब डॉलर का है। 2022-27 के बीच इसके सालाना 5.24 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है। उन्होंने कहा, 'इस बार दिवाली में जबरदस्त डिमांड रही। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को इसका अनुमान नहीं था। इससे टेम्परारी शॉर्टेज हुई। लेकिन इसके बाद पैनिक बाइंग के कारण स्थिति और बदतर हो गई।'

लिक्विड मिल्क को प्राथमिकता

इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक अमूल रोजाना 2.7 लाख लीटर दूध खरीदती है जबकि बटर प्रॉडक्शन सालाना 150,000 टन है। दूध में जीरो से 10 परसेंट फैट होता है जबकि बटर में यह 82 परसेंट और घी में 100 परसेंट होता है। 2021-22 में अमूल बटर की ग्रोथ 17 फीसदी रही जबकि घी का बिजनस 19 फीसदी बढ़ गया। सोढ़ी ने कहा कि कंपनी दूध की खरीद से जितना फैट बनाती है, उसमें से 60 परसेंट लिक्विड मिल्क में चला जाता है। बाकी दूसरे प्रॉडक्ट्स में जाता है। इसमें बटर भी शामिल है। उन्होंने कहा कि दिवाली के दौरान और उसके बाद सभी तरह के मिल्क प्रॉडक्ट्स में तेजी आई। इसमें लिक्विड मिल्क भी शामिल है। लिक्विड मिल्क प्रॉडक्शन कंपनी की प्राथमिकता है। जब भी इसकी मांग बढ़ी तो हमने मिल्क फैट के लिए आवंटन बढ़ा दिया। इस कारण हम बटर का प्रॉडक्शन नहीं बढ़ा पाए। लेकिन शॉर्टेज कुछ दिन के लिए थी और अब स्थिति सामान्य है। लेकिन दुकानों में अब भी अमूल बटर नहीं मिल रहा है। इंडस्ट्री के एक सूत्र ने कहा कि गायों में बीमारी इसकी वजह हो सकती है। लंपी बीमारी से कई राज्यों में गायों की मौत हुई है। अमूल बटर की कमी से निपटने के लिए रेस्टोरेंट्स वैकल्पिक उपाय कर रहे हैं।

भारत जी-20 में अंतरराष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन बनाने पर देगा जोरः पुरी

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत आगामी जी-20 बैठक में जैव ईंधन पर एक वैश्विक गठबंधन बनाने पर जोर देने की योजना बना रहा है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि बेहद सफल अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की तर्ज पर जैव ईंधन पर यह वैश्विक गठबंधन बनाने की योजना है। भारत अब कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के लिए गन्ने, अनाज और कृषि अपशिष्ट से तैयार जैव ईंधन को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है। भारत दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक देश है। पुरी ने यहां केपीएमजी के 'एनरिच 2022' सम्मेलन में कहा, ''हम अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की तर्ज पर एक अंतरराष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन बनाने के लिए अपनी जी20 की अध्यक्षता का उपयोग करेंगे।'' भारत एक दिसंबर को जी20 की अध्यक्षता संभालने वाला है। पुरी ने कहा कि भारत पहले ही गन्ने और अन्य कृषि उत्पादों से निकाले गए 10 प्रतिशत एथनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल (90 प्रतिशत पेट्रोल, 10 प्रतिशत एथनॉल) का उपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा, ''हमने पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण के लक्ष्य को पहले ही 2030 से घटाकर 2024-25 कर दिया है। जमीनी प्रयास के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस लक्ष्य को 2024-25 से पहले हासिल कर लिया जाएगा।'' जी20 में अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और चीन सहित कई प्रमुख जैव ईंधन उत्पादक देश शामिल हैं।

'सरकार को दवा क्षेत्र के लिये अलग मंत्रालय बनाने की जरूरत'

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार को घरेलू उत्पादकों को प्रोत्साहित करने तथा चीन से होने वाले आयात को नियंत्रित करने को लेकर दवा क्षेत्र के लिये अलग मंत्रालय बनाना चाहिए। क्षेत्र के समक्ष चुनौतियों पर औषधि कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) की गोलमेज बैठक में यह राय जाहिर की गयी। सीपीएचआई और पीएमईसी इंडिया के 15वें सत्र में कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की मंगलवार को हुई गोलमेज बैठक में घरेलू उद्योग के ध्यान को मात्रा की जगह मूल्य पर स्थानांतरित करने के तरीकों पर भी चर्चा की गयी।

आरपीजी लाइफ साइंस और फर्मेन्टा बॉयोटेक के सीईओ समेत अन्य कंपनी प्रमुखों ने प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिये चीन पर निर्भरता में कमी लाने की जरूरत भी बतायी। दवा बनाने वाली कंपनियों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्युटिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया (ओपीपीआई) के महानिदेशक विवेक सहगल ने कहा कि उद्योग को आईपीआर (बौद्धिक संपदा अधिकार) से संबंधित मुद्दों पर मिलकर काम करने और एकजुट होने की जरूरत है। बैठक में कंपनी प्रमुखों ने सरकार के समक्ष दवा उद्योग से जुड़े मामलों और शिकायतों को रखने के लिये एकल उद्योग संगठन बनाने पर भी चर्चा की। बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारियों ने कहा कि सरकार को घरेलू उत्पादकों को प्रोत्साहित करने तथा चीन से होने वाले आयात को नियंत्रित करने को लेकर दवा क्षेत्र के लिये अलग मंत्रालय बनाने चाहिए।

भारत-ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता 29 दिसंबर को लागू होगा

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) 29 दिसंबर से लागू होगा। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और पर्यटन मंत्री डॉन फैरेल ने बुधवार को एक बयान में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा कदम है जिससे पांच साल में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर 45-50 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। बयान में कहा गया है, ''(एंथनी) अल्बनीज सरकार इस पुष्टि का स्वागत करती है कि भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया-भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) के क्रियान्वयन के लिए अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा कर लिया है।'' उन्होंने कहा कि यह व्यापार समझौता 29 दिसंबर, 2022 से ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों और उपभोक्ताओं नई बाजार पहुंच के अवसर उपलब्ध कराएगा। इस समझौते पर इस साल दो अप्रैल को हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के तहत ऑस्ट्रेलियाई बाजार में कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी समेत 6,000 से अधिक व्यापक क्षेत्रों के भारतीय निर्यातकों को शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी। इसके अलावा समझौते से श्रम केंद्रित क्षेत्रों मसलन कपड़ा और परिधान, कुछ कृषि और मछली उत्पाद, चमड़ा, जूते, फर्नीचर, खेल के सामान, आभूषण, मशीनरी और बिजली का सामान को लाभ होगा।

अगले दो साल में डिजिटल अर्थव्यवस्था में रोजगार एक करोड़ पार कर जाने का लक्ष्यः वैष्णव

नयी दिल्ली। एजेंसी

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रों...इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टार्टअप और आईटी तथा आईटी संबद्ध सेवाओं... में अगले दो साल में रोजगार का आंकड़ा एक करोड़ के पार ले जाने का लक्ष्य रखा है। स्टार्टअप के लिये ईएसी-एसटीपीआई कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वैष्णव ने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के तीन बड़े स्तंभ हैं। वे हैं...इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, आईटी तथा आईटी संबद्ध क्षेत्र तथा स्टार्टअप। इन क्षेत्रों ने 88-90 लाख नौकरियां सृजित की हैं। मंत्री ने कहा, ''सरकार ने लक्ष्य रखा है। इसके तहत अगले दो साल में इन क्षेत्रों में रोजगार का आंकड़ा एक करोड़ के पार पहुंच जाना चाहिए।'' वैष्णव ने कहा, ''पहले स्टार्टअप के लिये कुछ शहरों का जिक्र होता था। अब जब मैं गांवों में स्कूल जाता हूं, वहां के बच्चे स्टार्टअप लगाना

चाहते हैं। यह बदलाव आया है।'' मंत्री ने कहा कि भारत अब प्रौद्योगिकी उपभोक्ता से प्रौद्योगिकी का जनक बन रहा है। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) स्टार्टअप को मंच प्रदान करने के लिये तमाम सुविधाओं से युक्त ढांचागत सुविधाएं तैयार कर रहा है। कार्यक्रम में मौजूद एसटीपीआई के महानिदेशक अरविंद कुमार ने कहा कि उनका संगठन स्टार्टअप के लिए 64 मझोले और छोटे शहरों (टियर दो और टियर तीन) में हर तरह की सुविधाओं से युक्त बुनियादी ढांचा (प्लग-एंड-प्ले) प्रदान कर है। उन्होंने कहा, ''हम उत्कृष्टता के जरिये स्टार्टअप को 5-10 लाख रुपये की शुरुआती पूंजी मुहैया कराते हैं। अगली पीढ़ी के पालना घर (इनक्यूबेशन सेंटर) योजना के तहत, हम मझोले और छोटे शहरों से आने वाले स्टार्टअप को 25 लाख रुपये का कोष देते हैं। हमने योजना के तहत लगभग 65 स्टार्टअप को लाभ प्रदान किये हैं और 2025 तक 300 स्टार्टअप को कोष देने का लक्ष्य है।''

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।